सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1073. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनेक सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सामूहिक आवास समितियों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त सामूहिक आवास समितियों में से कितनी समितियों को अब तक भूमि आवंटन कर दी गई है और कितनी समितियों भूमि आवंटित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है तथा इन समितियों को कब तक भूमि आवंटित कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) सहकारी सामूहिक आवास समितियों का पंजीकरण सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है तथा यह भूमि के आवंटन हेतु विचार करने के लिए पात्र समितियों के नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजता है । अगस्त और नवम्बर 1990 के दौरान, सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा भेजी गई ऐसी पात्र समितियों की सूची के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संलग्न सूची में निर्दिष्ट 423 समितियों को प्रस्ताव पत्र भेजे हैं । अभी तक इनमें से किसी भी समिति को भूमि आवंटित नहीं की गई है तथा इस समय यह बताना भी संभव नहीं है कि इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा ।

(देखिए परिशिष्ट 156, अनुबंध सं० 24)

Lowering the tariff for rail traction

1074. SHRI JITENDRABHAI LABHSHANKER BHATT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn to the news item which appeared, in Decean Kevald, dated the 9th September, 1990 under the caption "Lower power rate urged for rail traction".

(b) whether it is a fact that the Public Accounts Committee has urged the Department of Power to ask State Electricity Boards to lower the tariff for rail traction to reasonsable level to enable the Railways to speed up its electrification work;

(c) whether these instructions are being followed by all states; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) No, Sir. The Ministry of Energy (Deptt. of Power) have advised that the Electricity (Supply) Act 1948 does not contain any provision which enables the Central Government to issue direction to the State Govemments/Sftate Electricity Boards, and the State Governments have complete autonomy in regard to fixation of tariff.

Increasing of infrastucture facilities for tourists

1075. SHRI JAGADISH JAM: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa has given a proposal to the Central Government for 1990-91, for increasing infrastructural facilities "for tourists paticularly foreign tourists visiting that State;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) the steps taken thereon?